VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(10 July 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणाम
- भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन-सूचकांक
- **MCQs**

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणाम:

परिचय:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8-9 जुलाई, 2024 को रूस का आधिकारिक दौरा किया।
- दोनों पक्षों ने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की मजबूती और अपनी विदेश नीति प्राथमिकताओं के अभिसरण और पूरक दृष्टिकोण पर संतोष व्यक्त किया और इसे और मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रमुख शक्तियों के रूप में भारत और रूस बहुध्रुवीय दुनिया में वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- बयान में जम्मू-कश्मीर, दागेस्तान और मॉस्को में हुए आतंकी हमलों की निंदा की गई और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर से अधिक तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत-रूस के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति:

- दोनों पक्षों ने रक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग जैसे मुद्दों के साथ-साथ सहयोग के अन्य नौ प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की, जिनमें व्यापार, राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार निपटान, उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे नए मार्गों के माध्यम से कार्गो कारोबार में वृद्धि, कृषि उत्पादों, खाद्य और उर्वरक में व्यापार की मात्रा में वृद्धि, परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बातचीत को मजबूत करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश और संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देना, दवाओं की आपूर्ति पर सहयोग करना और मानवीय सहयोग का विकास करना शामिल हैं।

व्यापार और आर्थिक साझेदारी:

- दोनों पक्षों ने 2023 में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया, जो नेताओं द्वारा 2025 के लिए निर्धारित 30 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य का लगभग दोगुना है।

- दीर्घावधि में संतुलित और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापार हासिल करने के लिए, नेताओं ने औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने, विशेष रूप से उन्नत उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नई तकनीकी और निवेश साझेदारी बनाने और सहयोग के नए रास्ते और रूप खोजने के माध्यम से रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को और तेज करने और बनाए रखने के उद्देश्य से, नेताओं ने 2030 तक 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को और अधिक गहन बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने तथा दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में गतिशील वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखने की मंशा और इसकी मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने की इच्छा से प्रेरित होकर, संबंधित एजेंसियों को 2030 तक रूसी-भारतीय आर्थिक सहयोग के आशाजनक क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यक्रम (कार्यक्रम-2030) तैयार करने के निर्देश दिए।
- मुद्रा निपटान प्रणाली: लेनदेन को सरल बनाने के लिए व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को लागू करना। इस व्यवस्था के तहत भारत को रूसी आयातों के लिए

भारतीय रुपये में भुगतान करने की अनुमति है। यही व्यवस्था रूसी रूबल के मामले में भी लागू होती है।

- व्यापार में बाधाओं को दूर करना:
  - ➢ व्यापार में गैर-टैरिफ/टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए, जिसमें सुरक्षात्मक उपाय और प्रशासनिक बाधाएं शामिल हैं, नेताओं ने भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते के लिए पूर्ण वार्ता शुरू करने के लिए मार्च 2024 में प्रारंभिक बैठक की सराहना की।
  - ➢ नेताओं ने अपने संबंधित अधिकारियों को सेवाओं और निवेश में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत शुरू करने की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) यूरेशिया के पांच पूर्व सोवियत संघ राज्यों: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस का एक आर्थिक संघ है।
- बुनियादी ढांचे का विकास: दोनों देश बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल उत्पादन, जहाज निर्माण, अंतरिक्ष और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे। वे सहायक कंपनियों और औद्योगिक

समूहों का निर्माण करके भारतीय और रूसी कंपनियों के एक-दूसरे के बाजारों में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की योजना बना रहे हैं।

परिवहन और संपर्क बढ़ाने पर बल:

- दोनों पक्षों ने स्थिर और कुशल परिवहन गलियारों की एक नई वास्तुकला के निर्माण पर अपने दृष्टिकोण साझा किए और यूरेशिया में आशाजनक उत्पादन और विपणन श्रृंखलाओं के विकास पर पूरा ध्यान दिया, जिसमें ग्रेटर यूरेशियन स्पेस के विचार को लागू करने का उद्देश्य भी शामिल है।
- इस संदर्भ में, दोनों पक्षों ने चेन्नई-व्लादिवोस्तोक (पूर्वी समुद्री) गलियारे और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के कार्यान्वयन के साथ-साथ उत्तरी समुद्री मार्ग की क्षमता का उपयोग करने सहित बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हुए रसद लिंक का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की तत्परता व्यक्त की।
- दोनों पक्ष कार्गो परिवहन के समय और लागत को कम करने तथा यूरेशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए INSTC मार्ग के उपयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास जारी रखेंगे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:

- दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत और व्यापक सहयोग के महत्व को दोहराया, जो विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस संदर्भ में, दोनों पक्षों ने ऊर्जा संसाधनों में द्विपक्षीय व्यापार के निरंतर विशेष महत्व को नोट किया और नए दीर्घकालिक अनुबंधों की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों पक्षों ने कोयला क्षेत्र में चल रहे सहयोग की सराहना की और भारत को कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने और रूस से भारत को एन्थ्रेसाइट कोयला निर्यात करने के अवसरों की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की।

रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक में सहयोग:

- दोनों पक्षों ने रूसी संघ के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। इस संबंध में, दोनों पक्षों ने 2024-2029 की अवधि के लिए रूसी सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया, साथ ही रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग के सिद्धांतों पर भी हस्ताक्षर किए।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- सहयोग का यह कार्यक्रम भारत और रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के बीच आगे के सहयोग के लिए आवश्यक रूपरेखा प्रदान करेगा, विशेष रूप से कृषि, ऊर्जा, खनन, जनशक्ति, हीरे, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री परिवहन आदि के क्षेत्रों में।

असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष में सहयोग:

- दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के महत्व को नोट किया। दोनों पक्षों ने रूसी डिजाइन के VVER 1200, उपकरणों के स्थानीयकरण और एनपीपी घटकों के संयुक्त विनिर्माण के साथ-साथ तीसरे देशों में सहयोग पर तकनीकी चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
- अंतरिक्ष में सहयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रूसी राज्य अंतरिक्ष निगम "रोस्कोस्मोस" के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग में बढ़ी हुई साझेदारी का स्वागत किया, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, उपग्रह नेविगेशन और ग्रह अन्वेषण शामिल हैं। दोनों पक्ष रॉकेट इंजन के विकास, उत्पादन और उपयोग में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए।

सैन्य एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग:

- सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पारंपरिक रूप से भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का आधार रहा है, जो कई दशकों के संयुक्त प्रयासों और फलदायी सहयोग के माध्यम से मजबूती से आगे बढ़ा है। दोनों पक्षों ने नियमित रक्षा और सैन्य संपर्कों पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।
- भारत की आत्मनिर्भरता की खोज के जवाब में, साझेदारी वर्तमान में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास, सह-विकास और संयुक्त उत्पादन की ओर उन्मुख हो रही है।
- दोनों पक्षों ने मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए स्पेयर पार्ट्स, घटकों, समुच्चयों और अन्य उत्पादों के भारत में संयुक्त विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना की जाएगी और साथ ही दोनों पक्षों की मंजूरी से पारस्परिक रूप से मित्रवत तीसरे देशों को निर्यात किया जाएगा।

आतंकवाद से निपटने में सहयोग:

- दोनों नेताओं ने स्पष्ट रूप से आतंकवाद और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हिंसक उग्रवाद की निंदा की, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क और सुरक्षित पनाहगाह शामिल हैं। उन्होंने 8 जुलाई 2024 को जम्मू और कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में सेना के काफिले पर, 23 जून को दागेस्तान में और 22 मार्च को मास्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए हाल के नृशंस आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि ये आतंकवादी हमले आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग को और मजबूत करने की चेतावनी देते हैं।
- दोनों पक्षों ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़ाई का आह्वान किया। साथ ही आतंकवाद से निपटने में राज्यों और उनके सक्षम अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।
- इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने, धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

डिजिटल अर्थव्यवस्था और चिकित्सा उन्नति:

- दोनों नेताओं ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें उच्च तकनीक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए शैक्षिक आदान-प्रदान और इंटर्नशिप शामिल हैं।
- वे दवाओं और उन्नत चिकित्सा उपकरणों के विकास और आपूर्ति में व्यवस्थित सहयोग को बढ़ावा देने और रूस में भारतीय चिकित्सा संस्थानों की शाखाएँ खोलने की संभावना तलाशने पर भी सहमत हुए।

कृषि क्षेत्र में सहयोग:

- इस समझौते में कृषि उत्पादों, खाद्य और उर्वरकों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं। दोनों पक्षों का लक्ष्य पशु चिकित्सा, स्वच्छता और फाइटोसैनेटरी प्रतिबंधों और निषेधों को हटाने के लिए गहन बातचीत जारी रखना है।

मानवीय सहयोग:

- इस शिखर सम्मेलन में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में मानवीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- दोनों पक्षों ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर रूसी-भारतीय अंतर-सरकारी आयोग को इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने और अपनी अगली बैठक में प्रगति का आकलन करने का निर्देश दिया।

यूक्रेन मुद्दा:

- दोनों पक्षों ने रूस- यूक्रेन के बीच बातचीत और कूटनीति सहित यूक्रेन के आसपास संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से मध्यस्थता और अच्छे कार्यालयों के प्रासंगिक प्रस्तावों की सराहना की।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन-सूचकांक:

चर्चा में क्यों है?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्तीय समावेशन सूचकांक, जो देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को दर्शाता है, मार्च 2024 में 64.2 पर पहुंच गया, जो मार्च 2023 में 60.1 था।
- आरबीआई ने कहा कि सूचकांक में सुधार सभी उप-सूचकांकों में हुई वृद्धि के कारण हुआ है। यह सुधार मुख्य रूप से उपयोग आयाम के कारण हुआ है, जो वित्तीय समावेशन की गहनता को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन क्या होता है?

- वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि व्यक्तियों और व्यवसायों के पास उपयोगी और किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच है जो उनकी आवश्यकताओं - लेनदेन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा - को जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से पूरा करती हैं।

- वित्तीय समावेशन का गुणक प्रभाव समग्र आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देने, गरीबी और आय असमानता को कम करने और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में पड़ता है।
- उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक वित्तीय समावेशन को अत्यधिक गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानता है। साथ ही वित्तीय समावेशन को 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7 के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में पहचाना गया है।

RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 17 अगस्त, 2021 को वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक) लॉन्च किया, ताकि कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसों के लिए सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं, समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को ट्रैक किया जा सके।
- Fi-सूचकांक एक व्यापक सूचकांक है, जिसमें सरकार और संबंधित क्षेत्र के नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, साथ ही पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है।

- RBI ने देशभर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए FI-सूचकांक का निर्माण किया है। सूचकांक 0 से 100 के बीच एकल मान में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी को कैप्चर करता है, जहाँ 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण का प्रतिनिधित्व करता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
- RBI हर साल जुलाई में वार्षिक रूप से Fi-सूचकांक प्रकाशित करेगा।

वित्तीय समावेशन-सूचकांक के पैरामीटर:

- RBI के अनुसार, FI-सूचकांक में तीन व्यापक पैरामीटर शामिल हैं- पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता - प्रत्येक का अलग-अलग भार होता है। वित्तीय संस्थानों तक पहुँच का भार 35 प्रतिशत, उपयोग का 45 प्रतिशत और गुणवत्ता का 20 प्रतिशत होता है।
- यह सूचकांक सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में आसानी, सेवाओं की गुणवत्ता और सेवाओं तक पहुंच के प्रति उत्तरदायी है, जिसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं।
- सूचकांक की एक अनूठी विशेषता गुणवत्ता पैरामीटर है, जो वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवाओं में असमानताओं और कमियों द्वारा परिलक्षित वित्तीय समावेशन के गुणवत्ता पहलू को दर्शाता है।

- एफआईई-सूचकांक बिना किसी 'आधार वर्ष' के बनाया गया है और इस तरह यह वित्तीय समावेशन की दिशा में वर्षों से सभी हितधारकों के संचयी प्रयासों को दर्शाता है। रिज़र्व बैंक के अनुसार, मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक FI-सूचकांक 53.9 था, जबकि मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए यह 43.4 था वहीं मार्च 2024 में 64.2 पर पहुंच गया।

RBI द्वारा वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए कदम:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 जनवरी, 2020 को वित्तीय समावेशन 2019-2024 के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की।
- **RBI के वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के छह रणनीतिक उद्देश्य:**

1. वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच,
2. वित्तीय सेवाओं का बुनियादी गुलदस्ता प्रदान करना,
3. आजीविका और कौशल विकास तक पहुँच,
4. वित्तीय साक्षरता और शिक्षा,
5. ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण, और
6. प्रभावी समन्वय।

MCQs

1. 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य 'व्यापार और आर्थिक साझेदारी' के पहलू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को और तेज करने और बनाए रखने के उद्देश्य से, 2030 तक 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
   2. दीर्घावधि में संतुलित और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापार हासिल करने के लिए रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans: (c)

2. चर्चा में रहे यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU), रूस के नेतृत्व में पांच पूर्व सोवियत संघ राज्यों का संघ है। इस संघ में निम्नलिखित कौन-सा देश शामिल नहीं है?

(a) आर्मेनिया

(b) बेलारूस

(c) किर्गिस्तान

(d) अज़रबैजान

Ans. (d)

3. भारत और रूस के मध्य 'सैन्य एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. दोनों पक्षों ने मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के भारत में संयुक्त विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर सहमति हैं।

2. हालांकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से रूसी मूल के हथियारों के भारत में संयुक्त विनिर्माण केवल भारतीय सेनाओं के उपयोग के लिए होगा निर्यात के लिए नहीं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (a)

4. हाल ही में चर्चा में रहे वित्तीय समावेशन सूचकांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब लांच किया गया था?

(a) अप्रैल, 2017 में

(b) अगस्त, 2021 में

(c) नवंबर, 2021 में

(d) अप्रैल, 2023 में

Ans. (b)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

5. चर्चा में ;RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक; के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. इस सूचकांक में समान भार वाले तीन व्यापक पैरामीटर- पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता शामिल हैं।

2. इस सूचकांक के लिए 2017 को 'आधार वर्ष' के रूप में अपनाया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (d)